nent employees on par with the employees of the Handloom sector of the same Board.

I demand that the Minister concerned make a statement in the House, declaring all the employees of the All India Handicrafts Board permanent.

(v) Industrialisation of Eastern Uttar Pradesh to meet un employment problem among the Youth.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का एक पिछड़ा हिस्सा है, में भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है। अनेक युवक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार हो कर दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मिल रहा है, जिसे कर के वे अपना जीवन-यापन कर सकें। बेकारी की यह स्थिति घोर चिन्ताजनक है, जो असंतोष और हिंसा को जन्म दे रही है तथा युवा-शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसा देश का एक पिछड़ा हिस्सा पिछड़ा ही रह जा रहा है। अतः उक्त क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने तथा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वहां पर औद्योगिक विकास किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। इस लिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए युद्धस्तर पर उक्त क्षेत्र का औद्योगिक विकास किया जाए, ताकि युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। राष्ट्रीय एवं जनहित की दृष्टि से इस कार्य का किया जाना अत्यावश्यक है।

(vi) De-canalisation of Export of of Onions to Malaysia.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): The External Affairs Minister while in Malaysia during October had promised the Malaysian Industries and Trade Minister, to look into the plight of 30 Malaysian importers of Onions from India.

This assurance needs now to be followed up by action in India.

Malaysia imports about 50,000 tonnes of Onions annually from India. Until. 1974, the exports of Onions from India was under open general licence (OGL). On 16-11-1974, the Government canalized the exports through NAFED, and the scheme worked without harm till 11-6-1981, when the NAFED decided to canalize the entire quta of 50,000 tons through a single buyer. This decision has led to great hardship for the traditional exporters in India, especially in Nagapattinam in Tamil Nadu and to the traditional importers in Malaysia.

The price of Onions at c.i.f. in Penang, Malaysia, is only one-half of the market price there, implying that about Rs. 5 crores of illegitimate profits are being earned by this single buyer. Why should NAFED favour this concern ? There are disturbing reports of irregularities .

I demand that the Minister of Agriculture probe into this matter immediately and order the decanalization of the export of Onions.

(vii) Relaxation in Rules re grant of DA, CCA, HRA to the employees of Bharat Heavy Electricals unit and Small Arms Factory near Tiruchirapalli.

SHRI N. SELVARAJU (Tiruchirapalli): The Bharat Heavy Electricals unit employing about 20,000 personnel and also the small Arms Factory employing 7000 people are located just about 12 Kilometres away from Tiruchirapalli. The State Government has also set up its offices in this area. The employees of the State Government get DA, City Compensatory Allowance and House Rent Allowance. But, due to the rule that to become eligible for DA, CCA and HRA there should be the limit of 8 kilometre distance from the town, there is reluctance to sanction DA, CCA and HRA because of the distance of 12 Kilometres. Such a large number of employees should not be denied their dues because of this rule. The rule may kindly be relaxed so that they become eligible for DA, HRA and CCA, as a special case. If the genuine demand of these employees is not met forthwith, the employees will be compelled to resort to other actions.

(viii) Need for improving Working Conditions in Vinod and Vimal Textile Mills of Madhya Pradesh.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मध्य प्रदेश में उज्जैन की विनोद और विमल कपड़ा मिल के पिछले कई महीनों से नियमित न चलने के कारण इन मिलों में काम कर रहे हजारों मजदूर और कर्मचारियों की आजीविका को खतरा हो गया है। इन मिलों में अघोषित तालाबंदी के कारण जब जब मजदूर काम के लिए मिलों में जाता है मिल बंद होने की सूचना जिस में

बिजली प्रदाय अथवा और कोई कारण दर्शाया होता है "मिल बंद रहेगी" सूचना पढ़ कर वापस निराश लौटने को बाध्य हो जाता है। कई कई महीनों से मिलों की इस स्थिति के कारण मजदूर परिवारों को आर्थिक विपन्नता और अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। विनोद और विमल कपड़ा मिल की इस स्थिति के कारण जहां दस हजार से अधिक मेहनतकारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है वहीं इन पर आश्रित पचास हजार लोग असहाय हो गये हैं।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मिलों के प्रबन्ध और व्यवस्था में तत्काल सुधार करें तथा मिलों को नियमित चला कर हजारों मजदूरों और उन के आश्रितों को राहत प्रदान करें।

14.39 Hrs

KHUDA BAKHSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY (AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up further consideration of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library (Amendment) Bill. Shrimati Krishma Sahi may now speak.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करती हूं। भारत सरकार देश की कई ऐसी संस्थाओं को जिन का साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व रहा है उन को अपने अधीन करने जा रही हैं और पहले भी कई ऐसी संस्थाओं को उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में परिणित करने का निर्णय लिया है। ऐसी संस्थाओं पर सरकार का व्यय बहुत होता है। भवन निर्माण के लिए भी सरकार एड देती है लेकिन प्रश्न यह है कि जो सरकारी व्यय ऐसी संस्थाओं पर होता है उसका लाभ कहां तक पहुंचता है, कितने लोग उससे लाभान्वित होते हैं। सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुस्तकालयों के भवन का निर्माण नहीं होता बल्कि उस राशि का डाइवर्जन हो जाता है तथा रख-रखाव के नाम पर भी काफी बड़ी राशि का अपव्यय होता है।

जिस खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के ऊपर इस समय यहां चर्चा चल रही है वह पटना में है। पटना का जितना पुराना इतिहास हमारे पास है वह पटना हजारों साल पहले पाटलीपुत्र था, जिसका विश्व में अपना एक स्थान था। उसी प्रकार से खुदा बख्श लाइब्रेरी का भी इतिहास बहुत पुराना है। एक व्यक्ति विशेष की साहित्य में कितनी दूर तक अभिरुचि थी, उसका यह पुस्तकालय एक प्रतीक है। खुदा बख्श लाइब्रेरी में विश्व की सबसे बेहतरीन मुस्लिम साहित्य का संग्रह है और वहां की पाण्डुलिपियां बहुत ही रेयर हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी जोकि एक व्यक्ति विशेष की साहित्यिक अभिरुचि की प्रतीक थी, उसके अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए थी, उसको उन्होंने 1891 में जनता के उपयोग के लिए दे दिया। उस समय से बिहार सरकार इसके प्रबंध को अपने हाथ में लिए हुए है। लेकिन सन् 1962 में भारत सरकार ने एक हाई पावर बोर्ड का गठन किया और 1969 में पार्लमेंन्ट के द्वारा एक विधेयक पारित करा कर खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ऐक्ट बनाया गया। तबसे एक कमेटी इसका प्रबन्ध चला रही है जोकि डिपार्टमेन्ट आफ कल्चर, भारत सरकार के अधीन है। लेकिन केवल समिति बना देने से ही इस लाइब्रेरी में जो काम हो रहा है, वह संतोषजनक नहीं है।

इस स्तकालय में 1549 से पहले तक की मैनुसक्रिप्ट्स हैं जोकि हमारे पुरातन इतिहास की साक्षी हैं। वहां पर दस हजार वसैज हैं जो अभी अधूरी हैं। अली मदान खां, जोकि काबुल के गवर्नर थे, उन्होंने शाहजहां को उपहार के रूप में यह दी थीं। इस प्रकार से इस लाइब्रेरी का अपना एक करैक्टर है। इसमें बाबर, हुमायूं के हाथ की लिखी हुई कुरान है जोकि विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। दुनिया में जो संस्कृति, कला और सभ्यता का इतिहास रहा है उसको यहां पर अमात्व प्रदान किया गया है। जिन व्यक्तियों को साहित्य और कला से इतनी अभिरूचि थी उनको अमरत्व प्रदान करने के लिए इससे अच्छी निधि और क्या हो सकती है। इस संस्था का अच्छे ढंग से संचालन हो और उसका आम जनता को लाभ पहुंचे इस ओर मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नाम ही ओरिएण्टल लाइब्रेरी है और ओरिएण्टल शब्द में केवल उर्दू और अरबी ही नहीं आती है बल्कि संस्कृत और पाली भी इसमें आ जाती है।

फिलहाल इस लाइब्रेरी के चेयरमैन बिहार के गवर्नर साहब हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह होगा चूंकि यह ओरियन्टल लाइब्रेरी है, तो इसमें संस्कृत और पाली आदि ऐसी भाषाओं का भी संग्रह